जनजाति क्षेत्र से जुड़े सुझावों को बजट में समाहित किया जाएगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुक्रवार को जनजाति विकास के हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा की

जयपुर, 9 जनवरी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजाति विकास के हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेणेश्वर धाम व मानगढ़ धाम को ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है। बेणेश्वर धाम में सोम, माही व जाखम नदी के संगम पर विशाल आदिवासी मेले को और भव्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।**

समाज से विशेष जुड़ाव होता है और वे समाज की चुनौतियों और आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित होती हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनजाति क्षेत्र से जुड़े सुझावों को आगामी बजट में समाहित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे प्रदेश में जनजाति कल्याण को नई दिशा मिल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजाति विकास के हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा की।

सके।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनजाति संस्कृति तथा वैभव को संरक्षित करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार बेणेश्वर धाम तथा मानगढ़ धाम को ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर विशाल आदिवासी मेले को और भव्य बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी को जनजाति इतिहास और संस्कृति से जोड़ा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गत बजट में जनजाति विकास कोष की राशि को एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक हजार 750 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।

बैठक में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूंबर, बारां, सिरोही सहित, प्रदेश के विभिन्न जिलों के जनजाति कल्याण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत संरचना, रोजगार, सिंचाई सहित, जनजाति कल्याण से जुड़े विषयों पर सुझाव दिए।

इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास कुंजी लाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनजाति क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रुस के जब्त किए टैंकर से दो लोगों की रिहाई

मास्को, 09 जनवरी। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े गए रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मैरिनेरा के रूसी चालक दल के दो सदस्यों को रिहा करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले का स्वागत किया है।

मंत्रालय ने जारी किए एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह कदम क्रेमलिन के एक अनुरोध के जवाब में उठाया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

- **ये दोनों व्यक्ति रशियन हैं और रुस ने इनकी रिहाई के लिए ट्रंप को धन्यवाद कहा।**

इससे पहले, बुधवार को अमेरिकी यूरोपीय कमान ने स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मैरिनेरा को जब्त करने की घोषणा की थी। अमेरिकी युद्धपोतों ने कैरिबियन सागर से ही इस टैंकर का पीछा किया था। बेला वन, के पुराने नाम वाले इस टैंकर को वेनेजुएला के तेल निर्यात से संबंधित अमेरिकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के आरोप में रोका गया था। इस जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे जिनमें दो रूसी, 17 यूक्रेनी, तीन जॉर्जियाई और तीन भारतीय नागरिक शामिल हैं। अमेरिका ने पिछले साल के अंत में इस टैंकर पर तब नजर रखनी शुरू की थी जब इसने वेनेजुएला के पास जाने की कोशिश की थी। उस समय टैंकर के कप्तान ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जहाज पर चढ़ने की मांग को ठुकरा दिया था और अटलांटिक महासागर की ओर अपना रास्ता बदल लिया था।

खाजूवाला के पास ढाई करोड़ रूपए की हैरोइन पकड़ी

बीकानेर, 9 जनवरी (निसं)। भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। खाजूवाला उपखंड क्षेत्र के चक 40 केजेडी इलाके में पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने करीब आधा किलो हेरोइन जब्त की है। जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ढाई करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई बीएसएफ बीकानेर इंटेलिजेंस से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हेरोइन ड्रोन के जरिए सीमा पार से फेंकी गई थी। हालांकि इस मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

जानकारी के अनुसार, बीते कुछ दिनों से बीएसएफ की जी ब्रांच को बॉर्डर एरिया में हेरोइन तस्करी को लेकर लगातार इनपुट मिल रहे थे। खासतौर पर घने कोहरे के चलते तस्करों द्वारा

- **घने कोहरे की आड़ में सीमा पार से ड्रोन द्वारा यह हैरोइन फेंकी गई थी।**

ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भेजे जाने की आशंका जताई जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ इंटेलिजेंस पूरी तरह सतर्क थी और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन की रणनीति बनाई गई। अलसुबह खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ की टीम ने चक 40 केजेडी क्षेत्र में संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे खोलने पर उसमें करीब 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारियों को सूचना दी गई और क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला और खाजूवाला थाना एसएचओ सुरेन्द्र प्रजापत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। बीएसएफ के जवानों ने भी इलाके में गश्त बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ की टीमें आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं, ताकि तस्करों का कोई सुराग मिल सके।

पुलिस द्वारा जब्त किए गए पैकेट पर एक गोल मुहर लगी हुई है। मुहर पर '111' और '2023' अंकित है। इसके अलावा मुहर पर एक लॉयन की आकृति बनी हुई है और साथ में अंग्रेजी में लायन लिखा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस मुहर के जरिए तस्करी नेटवर्क से जुड़े सुराग जुटाने में लगी हुई हैं। मामले के बाद से सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। ड्रोन मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है और रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पहुंचने के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बरामद हेरोइन को सुरक्षित रखवाया गया है।

रुस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी

मास्को, 09 जनवरी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग करते हुए यूक्रेन की महत्वपूर्ण सुविधाओं पर बड़ा हमला किया। मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में उच्च सटीकता वाले लंबी दूरी की जमीनी एवं समुद्री हथियारों के साथ-साथ लड़ाकू ड्रोन भी शामिल थे। इसने आगे कहा कि लक्ष्यों में ड्रोन उत्पादन सुविधाएं और यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक परिसर के संचालन में सहायक ऊर्जा अवसंरचना शामिल थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल उच्च गति प्राप्त करने में सक्षम है। नवंबर 2024 में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पुष्टि की थी कि रूस ने मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया और यूक्रेन के निप्रो शहर में लक्ष्यों को निशाना बनाया। मंत्रालय ने कहा कि यह हमला 30 दिसंबर, 2025 की रात नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर लंबी दूरी के हमलावर ड्रोनों द्वारा किए गए कथित यूक्रेनी हमले के जवाब में किया गया।

संसद का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का अभिभाषण होता है और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों की परंपरा के अनुसार, इसके अलगे दिन एक फरवरी को बजट पेश किया जाता है।

पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर और बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद अवकाश के दौरान संसद की समितियां बजट पर मंत्रालय-वार विस्तृत चर्चा करती हैं। दूसरे चरण में वित्त विधेयक और अनुदान मांगों पर चर्चा होती है और उन्हें पारित किया जाता है।

आई पैक पर ईडी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिंघवी ने कहा, "ईडी अब राजनीतिक सलाहकारों पर छापे मार रहा है, क्योंकि वह तथ्यों, सच्चाई या विश्वसनीयता पर छापे मारने में असफल हो चुका है। कोलकाता में आई पैक पर छापा भाजपा के दबाव की नीति का एक और उदाहरण है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक हो जाता है, तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।"

संयोगवश, सिंघवी ने कई हाई प्रोफ़ाइल मामलों में ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व किया है।

हालांकि, इस मामले पर राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पांच बार के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने एक बिलकुल अलग राय व्यक्त की, जिन्होंने ईडी की कार्रवाई के प्रति ममता बनर्जी की घबराहट पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को आई पैक के बारे में क्यों सिरदर्द हो रहा है? इसके पीछे निश्चित रूप से कोई रहस्य है।" संयोगवश, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, सुवेन्दु अधिकारी ने भी गुरुवार को वही सवाल उठाया था, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी की छापेमारी के दौरान जैन के आवास और आई पैक कार्यालय में घुसीं और कथित तौर पर कुछ फाइलें और इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ लेकर वहां से निकलीं।

अधिकारी ने कहा, "मुख्यमंत्री को एक निजी कॉर्पोरेट इकाई के कार्यालय पर ईडी के छापे को लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है?" ज्ञातव्य है कि आई पैक सन् 2020 से ही तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट-रणनीति एजेंसी के रूप में काम कर रहा है।

'जोधपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि वे जेल में चल रहे भ्रष्टाचार से मुंह नहीं मोड़ सकते। अदालत ने कहा कि इस मामले में भी यह पता लगाना अत्यन्त आवश्यक है कि कैदी कौन से सेल में बंद था, जब उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके साथ और कौनसे कैदी बंद थे, और उस सेल की निगरानी करना किस जेल अधिकारी की जिम्मेदारी थी। अदालत ने अपने आदेश में जांच के अनौपचारिक रवैये को देखते हुए कहा कि समय के साथ साक्ष्य और तथ्य धूमिल और नष्ट हो जाते हैं और सच का पता लगाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जांच त्वरित की जानी चाहिए।

अदालत ने इस मामले में जोधपुर सेन्ट्रल जेल के जेलर, जेल के अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को सत्यापन पत्र जारी कर बताने को कहा है कि किन स्थिति में कैदी की मृत्यु हुई थी। इस सत्यापन पत्र की कॉपी की प्रति जोधपुर मेट्रो के जिला जज को भी भेजी जायेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत में मारे गये कैदी के परिजनों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और त्वरित कार्रवाई के आदेश दिये।

अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई करेगी

उत्तराखंड सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है

देहरादून, 09 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले मे एक रिसॉर्ट की कर्मचारी अंकिता भंडारी की मौत और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा घोषित होने के बाद, मामले में किसी वीआईपी के शामिल होने से संबंधित दावों तथा लगातार चल रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस प्रकरण की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का फैसला किया और कहा कि इसके लिए संस्तुति की जा रही है।

प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किये जा रहे थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस

- **ज्ञातव्य है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन चल रहा है।**

मांग को लेकर 11 जनवरी को उत्तराखंड बन्द का आ ान किया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि इस मामले में सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन किया गया।

आरोप है कि रिसॉर्ट में अंकित भंडारी पर विशेष सेवा देने के लिए दवाब डाला गया था और इससे मना करने पर उसकी हत्या कर दी गयी थी। निचली अदालत ने इस मामले में रिसॉर्ट के मालिक समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी थी। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप में इस प्रकरण में किसी वीआईपी के भी शामिल होने की बात कही गयी है, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ।

राजकोट में भूकंप के झटके

भूकंप के झटकों के कारण प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी

राजको, 09 जनवरी। गुजरात के राजकोट जिले के जेतपुर, धोराजी, उपलेटा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गये। यहां एक के बाद एक, भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। यहां एक के बाद एक, भूकंप के करीब 7 झटके महसूस किए गए। बार-बार आ रहे भूकंपीय झटकों के चलते स्थानीय अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।

इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (आईएसआर) के डेटा के मुताबिक, शुक्रवार सुबह भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। सबसे तेज झटका सुबह 6:19 बजे महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3.8 थी, इसके बाद, सुबह 8:34 बजे तक कुल 7 झटके दर्ज किए गए। भूकंप के झटकों से डरे लोग घर छोड़ खेतों की ओर भाग गए।

आईएसआर रिपोर्ट के अनुसार,

- **पहला झटका सुबह 6.19 पर आया उसके बाद 8.34 तक 7 झटके आए सभी की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 से 3.8 नापी गई।**

इन सभी भूकंपों का केन्द्र मुख्य रूप से उपलेटा से 27 से 30 किलोमीटर दूर पूर्व-उत्तरपूर्व (ईएनई) दिशा में दर्ज किया गया। भूकंप की गहराई जमीन से 6.1 किलोमीटर से 13.6 किलोमीटर के बीच थी। इससे पहले, कल रात 8:43 बजे इसी क्षेत्र में 3.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था।

लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के कारण, जेतपुर, धोराजी और उपलेटा पंथकों के ग्रामीण इलाकों में लोग खुद को सुरक्षित करने के लिए घरों में रहने के बजाय सड़कों और खेतों में निकल आए। हालांकि, राहत की बात यह है कि इससे अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

'कार्यकर्ता एनसीपी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में सभी तनाव समाप्त हो गए हैं।"

एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने की थी। दो साल पहले जब उनके भतीजे अजित पवार ने विद्रोह किया था, तब पार्टी विभाजित हो गई थी। इसके बाद अजित पवार एनडीए में शामिल हो गए और उपमुख्यमंत्री बने।

अजित पवार को पार्टी का मूल नाम और मूल निशान "घड़ी" मिला, जबकि शरद पवार के गुट को नया नाम, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और नया निशान, "ट्रम्पैट" मिला।

दोनों गुटों ने पिंपरी-चिंचवड़ नगरपालिका चुनाव के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया है।

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी और अजित पवार की चचेरी बहन, ने भी पुष्टि की कि एनसीपी के दोनों गुट पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर पिंपरी-चिंचवड़ चुनाव के लिए एकजुट हुए हैं।

उन्होंने कहा कि "ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि यह गठबंधन अजित पवार के साथ जारी रहेगा या नहीं।"

सुले ने महाराष्ट्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी (शरद पवार) के शामिल होने और उनके मंत्री बनने की अफवाहों को भी खारिज किया और कहा, "जो लोग इस तरह की अफवाहों से खुश हैं, उन्हें ही यह बात करने दो।"

दिल्ली में सब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोहरे और कम विजिबिलिटी को ध्यान में रखकर छात्रों की सुरक्षा के लिए लागू की गई हैं।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 5-8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जिससे सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। इससे बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया था। आईएमडी ने भी शीत लहर और कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हो रही है। कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस या अतिरिक्त पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों (प्राइमरी और मिडिल) के लिए स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।

आतंकवाद पर पाकिस्तान का रुख बदलने तक निलम्बित रहेगी सिंधु जल संधि

विदेश मंत्रालय ने यह टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया

नयी दिल्ली, 09 जनवरी।) भारत ने पाकिस्तान की सिंधु जल संधि को भारत के लिए बाध्यकारी बताने की टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह संधि निलंबित है और सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रूख में बदलाव नहीं होने तक निलंबित ही रहेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां साप्ताहिक ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा ," सिंधु जल संधि पर भारत अपनी स्थिति कई बार स्पष्ट कर चुका है। यह संधि स्थगित है और तब तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद की गतिविधियों को बंद नहीं कर देता।"

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने

- **पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु जल संधि बाध्यकारी है और वह भारत द्वारा चिनाब व झेलम पर किए जाने वाले निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा।**

कहा है कि सिंधु जल संधि भारत के लिए बाध्यकारी है और वह चिनाब तथा झेलम नदी पर भारत की विकास परियोजनाओं के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठायेगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत ने कहा है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकता। भारत ने स्पष्ट कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक यह संधि स्थगित ही रहेगी। राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट क्षेत्र में अवैध कब्जे को हटाये जाने के बारे में पाकिस्तान की टिप्पणी से संबंधित सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि पहले पाकिस्तान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों के साथ खुद किस तरह का व्यवहार कर रहा है।

गौरतलब है कि अवैध कब्जे को हटाये जाने के मुद्दे पर पाकिस्तान ने टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया था कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अलग-अलग शहरों में क्यों गई। इसका विरोध करते हुए पीड़िता के वकील दिवेश शर्मा ने कहा कि पुलिस जांच में साबित है कि दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी। इसके अलावा, पीड़िता की ओर से बताए होटलों में दोनों के ठहरने का रिकॉर्ड भी मिला है। आरोपी ने मई माह में आईपीएल मैच के दौरान पीड़िता को होटल में मिलने बुलाया था और उसके साथ संबंध बनाए थे। इस दौरान पीड़िता के मना करने पर उसने उसे क्रिकेट में करियर बनाने में सहायता करने और पिता के केस में आर्थिक मदद की बात कही थी। इसके अलावा, घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी तो उसकी सहमति भी कोई मायने नहीं रखती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने प्रकरण के जांच अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए हैं।

क्या केन्द्र सरकार हिम्मत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत में लागू होने वाले सामान्य कानून मुख्यमंत्री की मर्जी से निलंबित हो जाते हैं। अब यह चुनावी साल में केन्द्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच सियासी खींचतान जैसा लग रहा है। ई.डी. के अधिकारियों को, उचित कानूनी आदेशों के बावजूद, अपना सामान्य काम करने से रोकना, अवैध खनन से जुड़े अहम सबूत चुराना और पैसों को हवाला के जरिए घुमाना, ये सभी काम कानून के तहत स्पष्ट अपराध हैं। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी अपने हंगामे जारी रखकर जीत हासिल करती हैं या केन्द्र सरकार में उनके खिलाफ कल किए गए अपराधों पर कार्रवाई करने का साहस है। इस संघर्ष का राजनीतिक असर पड़ना तय है। केन्द्र को उनके हर दबाव और धमकी के सामने अपनी दृढ़ता दिखानी चाहिए।

कल ई.डी. कोलकाता में आई-पैक कंसल्टेंसी के दफ्तर में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रहा था। तभी पहले डिप्टी कमिश्नर और फिर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने ई.डी. अधिकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश की।

जब ई.डी. अधिकारी अपने पहचान पत्र और वारंट दिखा रहे थे, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और उन्होंने खुद आई-पैक कार्यालय से सभी जरूरी कागजात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कंप्यूटर जब्त कर लिए और उन्हें अपने साथ ले गईं।

आश्चर्य नहीं कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस कार्रवाई को प्रवर्तन निदेशालय की जांच से जुड़े सबूत और आपत्तिजनक सामग्री की खुली चोरी बताया। यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत एक गंभीर अपराध है। इस काम की गंभीरता को जानते हुए और अपनी गलती छिपाने के लिए ममता ने, हमेशा की तरह, राजनीतिक ढाल का सहारा लिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में सड़क पर रैलियां निकालीं और आरोप लगाया कि ई.डी. उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़ी एक कंसल्टेंसी फर्म से सामग्री उठा ले गया है। इसके बाद ई.डी. ने कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मांगने की कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी के साथियों ने अदालत कक्ष को इस तरह जाम कर दिया कि ई.डी. के वकील भी वहां पहुंच नहीं सके। मजबूर होकर जज ने ई.डी. की याचिका पर सुनवाई टाल दी और नई तारीख तय कर दी।

'वर्ष 2025 में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने में असहज थे, इसलिए मोदी ने फोन नहीं किया।" लटनिक ने यह भी कहा कि भारत समय-सीमा पूरी नहीं कर पाया, जिसके चलते अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सहित, कई एशियाई देशों के साथ व्यापार समझौते आगे बढ़ा दिए।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने आगे कहा कि इन एशियाई देशों के साथ हुए व्यापार समझौते ज्यादा ऊंची दरों पर किए गए, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत के साथ समझौता जल्दी पूरा हो जाएगा। लटनिक ने कहा, "जब भारत ने बाद में, समय-सीमा खत्म होने के करीब तीन हफ्ते बाद, अमेरिका से संपर्क किया, तो उसे बताया गया कि यह मौका अब खत्म हो चुका है।" अगस्त 2025 से भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले सामान पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया जा रहा है। अमेरिकी सरकार एक ऐसे विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में है, जो चीन और भारत जैसे उन देशों पर, जो रूस से तेल आयात करते हैं, 500 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की अनुमति देगा।

प्रियंका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को पूरी तरह से युद्धस्तरीय तैयारी करनी होगी, और सुनिश्चित करना होगा कि कोई कमी न छूट जाए।

प्रियंका ने सचिन पायलट को केरल के लिए मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जहां कांग्रेस पार्टी भारी आंतरिक कलह से जूछते हुए वापसी की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, वहाँ के.सी. वेणुगोपाल की बड़ी मौजूदगी भी है, जो कांग्रेस में सत्ता को नियंत्रित करते हैं।

प्रियंका को वेणुगोपाल की कार्यशैली ज्यादा पसंद नहीं है। वे यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि पार्टी वेणुगोपाल की दादागिरी के कारण हार न जाए। इसीलिए सचिन पायलट को भेजा गया है, ताकि प्रियंका को फीडबैक मिल सके और केरल में कांग्रेस नेताओं के बीच बराबरी का माहौल बने।

राजस्थान में, वेणुगोपाल अशोक गहलोत, डोटासरा, और रंधावा का समर्थन कर रहे हैं, और वे सचिन पायलट के साथ नहीं हैं। यही कारण है कि राजस्थान में संघर्ष और दिलचस्प हो गया है।

अगर कांग्रेस असम में जीत जाती है, तो प्रियंका के लिए यह एक बड़ी सफलता होगी, जिससे कांग्रेस की राजनीति और भी रोमांचक हो जाएगी।

अमेरिका वेनेज़ुएला में 9000 अरब रुपए का निवेश करेगा

वॉशिंगटन, 09 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वेनेज़ुएला पर अब और हमले नहीं किये जायेंगे और अमेरिका वहां 100 अरब डॉलर (करीब 9000 अरब रुपये) का निवेश करेगा।

वाइट हाउस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि वह वेनेज़ुएला में निवेश के लिए तेल कंपनियों के समूह से मुलाकात करेंगे।

उन्होंने लिखा है, "वेनेज़ुएला शांति

- **अमेरिका ने यह भी कहा कि अब वेनेज़ुएला पर हमला नहीं किया जाएगा**
- **वाइट हाउस के अधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्रंप के हवाले से कहा गया कि वे वेनेज़ुएला में निवेश के लिए तेल कंपनियों से बात करेंगे।**

की तलाश के संकेत के तौर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है। यह एक बहुत ही जरूरी और शानदार कदम है। इस सहयोग की वजह से पहले से उम्मीद की जा रही हमलों की दूसरी लहर को मैंने रद्द कर दिया है। इसकी जरूरत नहीं लगती। सुरक्षा के लिहाज से हालांकि सभी जहाज अपनी जगह पर रहेंगे।" इतना ही नहीं अमेरिका ने वेनेज़ुएला के साथ बदलते रिश्तों के भी संकेत दिये हैं और यह भी लिखा है कि अमेरिका वहां बड़ा निवेश करने वाला है। इसके लिए वह तेल कंपनियों के समूह "बिग ऑयल" से मिलेंगे। ट्रम्प ने लिखा, "अमेरिका और वेनेज़ुएला एक साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर जब बात अपने तेल और गैस के संरचनात्मक ढ ांचे को ज्यादा बड़े, बेहतर और ज्यादा आधुनिक तरीके से फिर से बनाने की हो।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600